PR PROFESSIONALS
Race for Excellence

Publication	Dainik Jagran
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No.	08
Date	25th July 2015

दैनिक जागरण

बिल्डरों से संबंधित शिकायतों पर होगी एक समिति

पूनम, गुड़गांव

शहर के लगभग 50 फीसद हिस्सों में स्थित बिल्डर लाइसेंस इलाकों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दो कमेटियां बनी हैं। अब तक कई सालों से बिल्डरों की मनमानी झेल रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है मगर इन दो कमेटियों को लेकर भी दुविधा की स्थिति है। हाल ही में रेडको के साथ उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में एक आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता कमेटी बनाई गई है। इसमें रेडको यानी रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य, हुडा प्रशासक, निगमायुक्त और अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस काउंसिल का काम परिवार न्यायालय की तरह मध्यस्थता का होगा मगर यह कमेटी आदेश नहीं जारी करेगी बल्कि दिशा निर्देश देगी। इस तरह इसके आदेश को बिल्डरों से बलपूर्वक नहीं मनवाया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर एक और कमेटी मुख्यमंत्री के आदेश पर बिल्डर लाइसेंस इलाकों के लिए रिड्रेसल ग्रीवेंस कमेटी बनी है। यह भी उपायुक्त की अध्यक्षता में है। इसमें बिल्डर लाइसेंस इलाकों की समस्याओं को लोग रख सकेंगे और अधिकारी समाधान कराएंगे।

दोनों कमेटियों को देखें तो यह इनका काम एक ही है। बिल्डर लाइसेंस एरिया में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान। अब तक लोग इन इलाकों में रहने वाले लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न हुडा के पास जा सकते थे न नगर निगम के पास। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को इनकी समस्याओं से कोई खास मतलब नहीं था। पिछले दिनों उपायुक्त पीसी मीणा ने एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई थी मगर यह काम नहीं कर सकी, उनका तबादला हो गया। दूसरी ओर अधिसंख्य बिल्डर लाइसेंस इलाकों में सीवेज, बिजली, सड़क, सामुदायिक भवन और ले आउट प्लान के नियमों के उल्लंघन, रखरखाव के नाम पर मोटी राशि के दोहन जैसी समस्याएं हैं।

कालोनाइजर इलाकों की समस्याओं के समाधान के लिए बनीं कमेटियां

आर्बिट्रेशन परिषद देश में इस तरह का पहला परिषद है। बिल्डर लाइसेंस इलाकों के लिए बनी हमारी कमेटी में शहर के अधिसंख्य बिल्डर जुड़े हैं। कुछ शिकायतें आ भी गई हैं। वेबसाइट के माध्यम से बिल्डर लाइसेंस इलाकों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। महीने में दो दिन हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में मध्यस्थता परिषद की बैठक होगी, इसमें अधिकारी शामिल होंगे। करीब 50 बिल्डर हमारे साथ इस कमेटी में शामिल हो गए हैं। ऑनलाइन शिकायत की जाएगी और हर महीने इसकी समीक्षा होगी। अगर कोई हमारे समझौते को नहीं स्वीकार करेगा तो वह कोर्ट जा सकता है। – कर्नल पृथ्वी नाथ, रेडको हरियाणा महासचिव।

संबंधित विभाग में लगातार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं

एक कर दी जाएगी दोनों कमेटियां

रेडको के साथ बने आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थ परिषद के कुछ सदस्यों को प्रशासन द्वारा बनाई गई शिकायत समिति को शामिल कर दिया जाएगा। दोनों कमेटियां एक कर दी जाएंगी। वो बिल्डरों को जिन्होंने लोगों की शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। -टीएल सत्यप्रकाश, उपायुक्त।